



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

C. K. Kany
11/85

नं. 529] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 30, 1984/कार्तिक 8, 1906
No. 529] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 1984/KARTIKA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 1984

आदेश

का.आ. 813(अ)/18कक/आई डी आर ए/84.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 874(अ)/18कक/आई डी आर ए/80 तारीख 3 नवम्बर, 1980 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) (बिहार राज्य में संयम मोतीपुर शूगर फैक्ट्री लिमिटेड, मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर नामक औद्योगिक उपक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन 2 नवम्बर, 1982 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, दो वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और बिहार स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड, पटना को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. 769 (अ)/18कक/आई डी आर ए/82 तारीख 30 अक्टूबर, 1982 द्वारा उक्त अवधि को 2 नवम्बर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया था ;

और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तारीख 29 सितम्बर, 1983 के अपने आदेश द्वारा यह निर्देश दिया था कि केंद्रीय सरकार उक्त औद्योगिक उपक्रम के प्रबंध ग्रहण करने की अवधि को, 2 नवम्बर, 1983 (यह तारीख जिसको उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने की अवधि को बढ़ाने वाली अधिसूचना समाप्त होने वाली थी) से परे और नहीं बढ़ाएगी और आगे यह भी निर्देश दिया था कि उक्त औद्योगिक उपक्रम बिहार स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधाधीन तब तक बना रहेगा जब तक कि रिट की यर्जी का निपटान नहीं हो जाता ;

और, उक्त उच्च न्यायालय ने तारीख 23 अप्रैल, 1984 के अपने आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार को यह निर्देश दिया था कि यह कंपनी और उसके निदेशकों को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने के लिए व्यक्तिगत अवसर प्रदान करने के पश्चात्,

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक के अधीन उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने की अवधि को 23 अप्रैल, 1984 से चार सप्ताह के भीतर बढ़ाए ;

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त उच्च न्यायालय के निर्देशों को अनुपालन करके भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 393 (अ)/18कक/आई डी आर ए/84 तारीख 19 मई, 1984 द्वारा, अवधि को 31 अक्टूबर, 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दिया था;

और कंपनी तथा उसके निदेशकों को एक नई सूचना दी गई है जिसमें प्रबंध ग्रहण की अवधि बढ़ाए जाने के सरकार के आदेश को प्रमाणित किया गया है और कंपनी और उसके निदेशकों को यह कारण बताने का अवसर दिया गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के प्रबंध ग्रहण की अवधि को बढ़ाए जाने का आदेश क्यों न किया जाए ।

और, कंपनी द्वारा या उसके निदेशकों द्वारा, उनको अनुज्ञात समय के भीतर कोई कारण नहीं बताया गया है ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम, बिहार शूगर कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के प्रबंध के अधीन 30 सितम्बर, 1985 तक को, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए बना रहे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 30 सितम्बर, 1985 तक को जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे ।

[फा सं. 4(13)/80-सी यू.एस]

ए. पी. सरवान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 30th October, 1984

ORDER

S.O. 813(E)/18AA/IDRA/84.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No S.O. 874(E)/18AA/IDRA/80, dated the 3rd November, 1980 (hereinafter referred to as the said order), the management of the industrial undertaking known as Messers Motipur Sugar Factory Limited, Motipur, District Muzaffarpur in the State of Bihar (hereinafter referred to as the said industrial undertaking), was taken over under clause (a) of sub-section (i) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of two years upto and inclusive of 2nd November, 1982 and the Bihar State Sugar Corporation Limited, Patna was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, the Central Government by an order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 769(E)/18AA/IDRA/82 dated the 30th October, 1982, extended the period by one year upto and inclusive of the 2nd November, 1983 ;

And, whereas, the High Court at Calcutta had, vide its order dated the 29th September, 1983, directed that the Central Government shall not make any further extension of the take over of the management of the said industrial undertaking beyond the 2nd November, 1983, (the date on which the notification extending the period of take over of the management of the said industrial undertaking was due to expire), and had further directed that the said industrial undertaking shall continue to be under the management of the Bihar State Sugar Corporation Limited till the disposal of the writ petition ;

And, whereas, the said High Court had, vide its order dated the 23rd April, 1984, directed the Central Government to extend, after giving the company and its director a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order, the period of take over of the management of the said industrial undertaking under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), within four weeks from the 23rd April, 1984;

And, whereas, while complying with the directions of the said High Court, the Central Government by an order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 393(E)/18AA/IDRA/84 dated the 19th May, 1984, extended the period upto and inclusive of the 31st October, 1984 ;

And, whereas, a fresh notice has been given to the Company and its director intimating the Government's intention to extend the period of take over and giving the company and its director an opportunity to show cause as to why an order of extension of the period of take over of the said industrial undertaking should not be made ;

And, whereas, no cause has been shown either by the company or by its director, within the time allowed to them ;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Bihar State Sugar Corporation Limited, Patna for a further period upto and inclusive of the 30th September, 1985 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the said Act, the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 30th September, 1985.

[File No. 4(13)/80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.